



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY



भाग I—काण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 1981/ज्येष्ठ 8, 1903

No. 116]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 1981/JYAISTA 8, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न ही जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य मंत्रालय

मार्बंजिक सूचना सं. 27-आई०टी०सी० (पी० एन०)/81

नई दिल्ली, 29 मई, 1981

आयात आपार नियंत्रण

विषय : 4 विलियन येन के विदेशी आर्थिक महयोग निधि (प्रो० ई० सी० एफ०) ऋण के अधीन हरियाणा राज्य विश्वनूत् बोर्ड द्वारा किए जाने वाले माल और सेवाओं के संबंध में लाइसेंस शर्तें

सिं. सं. आई० पी० सी०/23(15)/80-81—जापान की विदेशी आर्थिक महयोग निधि (प्रो० ई० सी० एफ०) द्वारा प्रदान किए गए 4 विलियन येन ऋण के अधीन हरियाणा राज्य विश्वनूत् बोर्ड की परिषद्मी यमुना नहर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की आयात आवश्यकताओं के विनावान के लिए आयात लाइसेंसों के नियंत्रण को नियंत्रित करने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिणाम में दी गई हैं, वे जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

प्र० रमेश मजुमदार, मूल्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण

परिचालन

जापान की विदेशी आर्थिक महकारी निधि (प्रो० ई० सी० एफ०) द्वारा प्रदान किए गए 4 विलियन येन ऋण के अधीन हरियाणा राज्य विश्वनूत् बोर्ड की परिषद्मी यमुना नहर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए माल के आयातों और सेवाओं के संबंध में लाइसेंस शर्तें:

खंड-1 सामान्य शर्तें

(1) हरियाणा राज्य विश्वनूत् बोर्ड (प्रो० ई० सी०) की परिषद्मी यमुना नहर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की आवश्यकताओं के विनावान के लिए जापान की विदेशी आर्थिक महयोग निधि (प्रो० ई० सी० एफ०) द्वारा प्रदान किया गया 4 विलियन येन का यूण विकासीय वेशों के लिए खुगा है। तबनुगार, इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत लासी वेशों से आयात की जा सकती हैं। मेरे देश इस ऋण के अन्तर्गत पावर स्लोट देश होंगे।

(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के निपटाइसें जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महान-निवेशालय तकनीकी विकास/विंगोगत माल मन्त्रित द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस (सी) का मूल्य 4,440 मिलियन (साप्तमीया-भाड़ा) येन में शार्थिक तरीं होगा क्राहिए।

आयात लाइसेंस का मूल्य स्पष्ट में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा-शुल्क) द्वारा अधिसूचित विनाय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की निधि को प्रचलित दर और मूल्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं. 78-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74, विनाय 6 जून, 1974 के दैग-2 के प्रतुमार आयात लाइसेंस में संकेतित दर पर नियंत्रित किया जाएगा। जिसमें यह भी उल्लेख है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत आयाती आयात लाइसेंस (सी) में विनियोग मुद्रा विनाय दर पर लाइसेंस मूल्य के नामे दालेंगे। लाइसेंस पर एक शीर्षक “जापानी येन ऋण संलग्न-आई० टी० पी०-7” होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में “एस०/ज० एन०” कोड होगा। एच०

एस० ई० बी० को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आधान-नियंत्रित के पत्र में भी ही दुहराया जाएगा। जिसको एक प्रति वित्त मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठाकृत की जानी चाहिए।

1(3) नागान शीमा-भाड़ा के आधार पर केवल एच० एस० ई० बी० के नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) एच० एस० ई० बी० की सुविधा पर निर्भर करने वाले एक से अधिक आयात लाइसेंस इच० केडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन, कुल मूल्य 4,440 मिलियन (नागान-शीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए और पैरा (1) में कहा गया है।

1(5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि एच० एस० ई० बी० द्वारा आवेदन करने पर 31-12-85 तक दी जा सकती है। इससे आगे की वृद्धि यदि कोई हो तो, आधिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजी जानी चाहिए।

1(6) केडिट के अधीन वित्तालय किए जाने वाले आयात आयात लाइसेंस से संबंधित माल और सेवाओं की सूची जो कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हो, तक प्रतिवंशित है।

1(7) विदेशी सुदा के किसी भी परेण्य की अनुमति आयात-लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकारी के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अधिकारी की भारतीय रुपां द्वारा में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1(8) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों की लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी द्वारे की नियंत्रित से 4 महीनों की अवधि के भीतर आधिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। भाड़ा और बीमा प्रधार का भुगतान भारतीय समय में भारत में किया जाएगा। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस द्वारा दिए गए उन कल्याणी प्रादेशों से है जो या या विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्तान्तरित हों या भारतीय आयातक या विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्तान्तरित अथ संविदा हो। विदेशी संभरकों के भारतीय अधिकारीओं के आदेश या ऐसे भारतीय अधिकारीओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का नद तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की नियंत्रित से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग, इच० १ अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबंध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की नियंत्रित से 8 महीनों में अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्राप्त निरपेक्ष रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त, मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई विल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रयोक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना नियंत्रित लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को परेवित करेंगे लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय प्राधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण

ठेकों में वैकं गारंटी साल्ल-न्यू स्पायिन करने के लिए प्राधिकारपत्र मुख्य रूपया जमा करने की स्वीकृति आवि की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवधि पूर्ण कर देने चाहिए। माल के पीछे लशन पर अनग-अनग भुगतानों की अवधि होनी चाहिए। ठेके में तकद आधार पर अर्थात् दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की अवधि होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक का किसी भी किल्म की अर्थ सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के निवरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अन्त्यार व्यवस्था होनी चाहिए।

"भाल्ल-न्यू की प्राप्ति के बाद 'महीने परन्तु अधिक' के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।"

पोन्तशन के लिए आधिकारी नियंत्रित करने में हस्त बात का व्यान रखना चाहिए कि यह नियंत्रित 31-12-84 के आद वी न हो।

अंड-2 संभरण ठेके का समझौता करने समय व्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें:

2(1)(क) ठेके का जहाज पर्यान्त निशुल्क मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपां में छुकाना चाहिए। भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। अब आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आवेदन के बाल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) ओ० ई० सी० एफ० येन केडिट (परियोजना महायता) के अधीन माल और सेवाएं प्रधिप्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश अनुबंध-2 में दिए गए हैं। लेकिन साधारणतया माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय संविदा के माध्यम से की जानी चाहिए और निम्नलिखित बातों की व्यान में रखा जाना चाहिए:—

(क) बोली लगाने के लिए निम्नक्रिया भारत में सामान्य रूप से परि आन्वित होने वाले कम से कम एक मासाचार पत्र में विज्ञाप्ति करने पड़ते हैं।

(ख) बोली के बाड़ या बोली लगाने की गारंटी की सामान्य आवश्यकता है परन्तु उनको इन्होंना उड़ान नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले, हतोन्ताहित हो जाएं।

(ग) बोली खुल जाने के बाब असफल बोलीकारों को यत्तारीषी बोली बाड़ या गारंटिया रिहा कर देनी चाहिए।

2(3) जिन भागलों में औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा उचित न हो वहाँ नियंत्रित निम्नलिखित यैकल्पिक नियाविधि अपनाएँगी:—

(क) जहाँ आयातक के पाम विश्वमनीय कारण हों या अपने उपम्भकर का उचित भानकीकरण रखता हो।

(ख) जहाँ पर पात्र संभरकों की संज्ञा सीमित हो।

(ग) जहाँ अधिप्राप्ति में शामिल धनराशि इसी कम हो कि विदेशी कर्वे स्पष्ट रूप से दिलचस्पी न में या औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा के कायदे शामिल प्रशासकीय भार से महत्वपूर्ण हों।

(घ) ऊपर (क), (ख) और (ग) के अन्तरिक्ष जहाँ नियंत्रित औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा का अनुकूलन करता अनुचित सभजे या नियंत्रित ऐसी प्रक्रिया का अनुपयुक्त समझे उवाहरणार्थ आपात अधिप्राप्ति के सामले में।

ऊपर मानकेतिक मामलों में निम्नलिखित अधिप्राप्ति प्रक्रिया इस दृष्टि से अपनाई जाए जिससे जहाँ तक उचित हो पूर्ण सम्भाव्य सीमा तक प्रभावशालिक छाली प्रत्यारूपीय निवाच प्रक्रिया का प्रयोग नहीं हो सके :—

(1) श्रोतवाचिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना ।
(2) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिवाचिक अधिश्वासन ।
(3) एक संभरक से सोधा क्या विशेष कारण, औचित्य लगाने वाली श्रोतवाचिकों के ।

एक एस ही बी को विशेष कारण /प्रौद्योगिक वतान चाला बोलियां के मूल्यांकन और सुनना पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये जिस पर न्यूनतम मूल्यांकित बोली आधारित हो। और इसकी सीन प्रतियों के साथ बोली विश्लेषण विवरण भीट, दस्तावेजों साथकों महित प्रादि कोई हो सो यिस मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नहू फिल्मी को भेजनी चाहिये जो उसका आवश्यक अनुमोदन विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ०१०सी०एफ०) से उसका आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करें। यह ध्यान में रखना चाहिये कि कल संविदा, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), (जापान अनुभाग) द्वारा ओ०१०सी०एफ० को केवल नभी अधिसूचित किया जाएगा जबकि रिपोर्ट प्रादि को ओ०१०सी०एफ० से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

(4) विशेष संभरक का भुगतान, उसके नाम में भारतीय बैंक द्वाकियों द्वारा 1979-80 के गिरंग त्रो है सी एफ बैंक ब्रेडिट (पर्सनलजनन सम्पादन) स० आई०डी० पी० 7 के अधीन खोले गये अपरिकृतनीय मालिक पद्ध के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका द्विरा नीचे खड़ 6 में दिया गया है।

2(5) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही सविदा की जानी चाहिये। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से प्रधानिक सविदा करने की अनुमति भी श्री जा सकती है जिसके लिये आयात लाइसेंस जारी होने की निष्ठि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, प्राधिक कार्यपालग (आयात अनुभाग) से अनमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2(6) सभरक की पालना : सभरक पाल खोत देशों का नागरिक या पाल लौत देशों के नागरिकों द्वारा यथार्थ रूप से शामिल वैध अधिकार होगा। उसे निम्नलिखित मार्ग पूर्ण करनी पड़ेगी :

(क) पात्र स्नोत देशों के नागरिकों द्वारा अधिकतर अभिदृष्ट मेयर रहे जाएंगे।

(ख) अधिकतर पृथकाधिक निवेशक पात्र स्नोत देशों के नागरिक होंगे।

(ग) ऐसे बैच अर्यन्ति पात्र स्नोत देशों में पंजीकृत होंगे।

(7) मंविदा में धोषणा, प्रत्येक मंविदा में संभरकों द्वारा पालन का निम्ननिखिल विवरण जोड़ा जाएगा।

‘मैं, अशोकस्त्रांशी एवंद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि संभगित किया जाने वाला माल मेरे (पात्र स्रोत देश) उत्पादित है।

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुमार अपाने दोनों से आयातिन भाग निम्नलिखित सूच के अनुमार 30 प्रतिशत में कम है।

ଆଯାତିନ ଯାଗନ ବୀମା ଭାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ-|-ଆଯାତିନ ଶୁଳ୍କ

Percent of total of feature $\frac{1}{\sqrt{2}}$

“मैं, भ्रष्टाक्षरी, एतद्वारा सत्यापित करना है कि
 (पात्र मोत तेंग का नाम) में (कपणी का नाम) ममाविष्ट
 और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र मोत तेंगों के नामगिरियों द्वारा नियंत्रि-
 ति दिया गया है।

(8) अपात्र क्षेत्र वेणों से अनुमेय आयातः जिन वस्तुओं में अपात्र क्षेत्र देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका वितरण किया जा सकता है वर्षों कि निम्नलिखित गूच के अनुसार मददार आधार पर आयातित भाग 30% से कम हो :—

प्रायातित सागत वीमा भाड़ा मूल्य + ग्रामातक शुल्क $\times 100^n$

सभाक का जहाज पर निःश्वास मूल्य

प्र० ३ संभरण ठेको मे समाविष्ट की जाने वाली शर्तः-

३(१) संभरण ठेकों मे निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से रामाविष्ट होने चाहिए:-

(क) ट्रेक की व्यवस्था भारत सरकार और जपान की विदेशी आर्थिक महत्वोंगति निधि (योंई सं.एफ.) के तीव्र गत एवं इसी बीड़ी पश्चिमी यमुना नदी द्वारा दूषित करने वाली जल के लिए येतन केडिट आई डी पां-7 (परियोजना नदीयता) से संबंधित 19 मार्च, 1981 को हुए कठुण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार श्रीर विदेशी आर्थिक महत्वोंगति निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(अ) सभकां के भुगतान, भारत मरकार और जापानी विदेशी आर्थिक महंगाग निधि (ओर्डरमैण्ट) के बीच येन क्रेडिट सं० आईपी-७ से संवेदित १८ मार्च, १९८१ को हुए अनु समझौते के अन्तर्गत बैंक श्राफ इडिया टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय सामग्री के भाव्यम से किए जाएँ।

(ग) यिदेही मंभरक गेस्टी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए महमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर आईसीएफ द्वारा येन अृण के अधीन प्रयोगित हो।

(घ) 2(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाणपत्र (तीन प्रतियों में)

3(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के संबंध में एक धारा हाँनी चाहिये कि जापानी संभरक भारतीय इनावास, टॉकियो के परामर्श पर पात प्रश्नहृत व्यवस्था बारने के लिये महसूल है और इस उद्देश्य के लिये वह भारतीय दूतावास, टॉकियो को, शामिल माल की सुरुदंगी के कार्यक्रम में प्रश्नगत करेगा और पात लदान से कम से कम 4 सप्ताह पूर्व भारतीय इनावास को मूचना देंगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। यिषेप मामलों में, जहाँ भारतीय आयातक हड्डूक हों। मूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक का प्रत्येक पात लदान के पश्चात् आशयक ल्यौरा देने होए तार से मूचना भेजने के लिये सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टॉकियो को भेजी जानी चाहिए।

खड 4—विवेशी आर्थिक महाकारिता निधि (प्र००९८३०६५०) द्वा०।
ठेके का अनुमोदन :—4(1) लाइसेंसधारी को प्रके आदेश देने के लिये
निर्धारित अवधि के भीतर एच०एस०४०वी० और विवेशी संभरक दोनों
द्वारा विषिक्त हस्ताक्षरित ठेके की जार प्रतियो जा॒ विवेशी संभरक द्वारा
विषिक्त में पुष्टि घादेश के माथ हो॑ या उनकी छृ॒ प्रकार मे॒ पूर्ण फोटो
प्रतियो संगत वैय आश्रात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियो महिन, जापान अनुभाग
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रा॑प ना॒ ना॒, नई दिल्ली को भेजी
जानी। चाहिए।

4(2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी टेकों के लिये और टेकों की विषय वस्तु के लिये अनिवार्य आंशोधनों के कारण संघोधनों पर उनकी बीमतों पर भी लापू होंगी।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग, एवं एम ई बी के परिचयीय मूलन नहर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिये वेन क्रेडिट स० याईटीपी-७ (परियोजना महापत्र) के अनुर्भव वित्तालय करने

के लिये विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओई सी एफ) को संविधा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिये भेजने की व्यवस्था करेगा।

खंड 5—विदेशी संभरकों को भुगतान साझा-पत्र क्रियाविधि:

5(1) विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओई सी एफ) से टेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग द्वारा एन्सोम ६००००० और महायाता नेत्रा तथा नेत्रा परीक्षा निवेदक को उसकी सूचना दे दी जायेगी। उपके बाद एच एस ई बी ई का गहायाता नेत्रा एवं नेत्रा परीक्षा निवेदक (जिसे हमके बाद मी०ए०ए००० कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, सेसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबंध-३ के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये अनुरोध करता चाहिए। सी ए ए एंड ए अनुबंध-४ के रूप में संलग्न प्रपत्र में एक प्राधिकारपत्र भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को अनुबंध-५ (आस्तविक आयातों के लिए) या अनुबंध-६ (सेवाओं के लिये) के रूप में संलग्न प्रपत्र में संबंधित विदेशी संभरक के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिये जारी करेगा। प्राधिकारपत्र की प्रतिवां (विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि) (ओई सी एफ) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत के आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी प्रृष्ठाकृत की जाएगी।

5(2) प्राधिकारपत्र मिलने पर, भारतीय बैंक टोकियो अनुबंध-५ (आस्तविक आयातों के लिये लागू होता है) या ६ (सेवाओं के लिये लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओई सी एफ) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी भेजेगा।

मी०ए०ए००० से प्राधिकारपत्र के आधार पर भाष्य-पत्र खोलने के लिये उपर्युक्त क्रियाविधि संविधा संशोधन या अन्यथा के लिये आवश्यक समझ जाने वाले ऐसे ही सभी प्राधिकार पत्र/साझा पत्रों के संशोधनों पर स्वतः लागू होंगी।

5(3) माल का पोत सदाचार करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के भाष्यम से साखपत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिये बैंक आफ इंडिया टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज भी पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उनके बैंकरों के भाष्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साझा-पत्र के अंतर्गत सौदे तथा करने के लिए यात्रा-पत्र खोलने के लिए टोकियो स्थित भारतीय बैंक को चुकाए जाने वाले बैंक प्रभार और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरक के बैंकर के प्रभारों के लिए और विदेशी संभरक को उनके द्वारा किए गए आयातों की कीमत के भुगतान की निधि से ओ० ६०० सी० एफ० द्वारा प्रतिपूर्ति की तारीख तक की व्यवधि के लिए आदा किए जाने योग्य व्याज प्रभारों का फैसला भारत सरकार के लेखों को प्रमाणित किए जिन्होंने ही सामान्य बैंकिंग सूत्र के भाष्यम से टोकियो स्थित भारतीय बैंक को प्रेषण द्वारा भारत में आयातक के बैंक द्वारा किया जाएगा।

भारतीय बैंक टोकियो द्वारा संभरक को माल के जहाज पर निश्चल मूल्य के भुगतान की तारीख और ओ० ६०० सी० एफ० द्वारा प्रतिपूर्ति की तारीख के बीच अन्तराल के लिए भारतीय बैंक २५-३-१९८० का भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ उनके द्वारा किए गए समझौते के नियम एवं शर्तों के अनुसार व्याज की वसुली करेगा और भारतीय दूतावास, टोकियो से उसकी प्रतिपूर्ति करवा देगा। जापान में भारतीय दूतावास द्वारा इस व्याज के भुगतान से हुए छें [खंड 6(4) के अनुसार] एच० एन० ६०० सी० से वसुल किए जाएंगे।

खंड 6—रूपया निष्क्रेप करने के लिए उत्तरदायित्वा—

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो संघत प्राधिकार पत्र के परिणाम में मकेतित अनुसार भारतीय बैंकर को परकार्य जहाजरानी दस्तावेज भेजेगा और बैंकर इसके बदले में यह मुनिष्यव्य करेगा कि जहाजरानी दस्तावेज द्वारा हीन से पहले भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निष्क्रेप कर दिया गया है। येन भुगतान के समनुरूप रूपए पर व्याज की दर प्रत्येक ३० दिनों के लिए १०% आर्थिक और उसमें प्रधिक प्रबंधि के लिए १५% आर्थिक होती, जो बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि में वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक गिनी जाएगी और भारतीय सूचना म० ४६-आई० ६०० सी० (पी० एन०)/७४ दिनांक १०-६-७६ के अनुसार सूल भुगतान के साथ जमा की जाएगी। यह नोट कर दिया जाना चाहिए कि दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया गया है और जिस दिन भरकारी लेख में रुपया जमा किया गया है, का व्याज दिया जाएगा। ऐसिंग भारतीय सूचना स० १०३-आई० ६०० सी० (पी० एन०)/७६, दिनांक १२-१०-७६ के अंतर्गत संशोधित सार्व-सूचना स० ७४-आई० ६०० सी० (पी० एन०)/७४ दिनांक १३-५-१९७४। विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समनुरूप रूपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनियम का दर भुगतान की तारीख को लागू विनियम की वह मिश्रित दर होती जो सार्व-जनिक सूचना स० १०४-आई० ६०० सी० (पी० एन०)/३-८-७५ और स० ५-आई० ६०० सी० (पी० एन०)/७६, दिनांक १७-१-१९७६ में निर्धारित नरीके के अनुसार निष्क्रित की गई हो जो मृत्यु नियवक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुश्त्रा विनियम नियन्त्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर धोषित की गई हो। जिस लेख थीर्थ में उपर्युक्त रूपया निष्क्रेप किया जाएगा वह “के डिपोजिटम एंड एडवांस्मेंट-४४३ सिविल डिपोजिटम डिपोजिटम कार परसेजिज एम्ट्रा एटशोड परसेज ऑडर फ्रेस्ट्रिम। लोन एप्रीमेंट लोन कोर्स वि गवंबनमेंट आफ जापान ४ विनियम येन फ्रेस्ट्रिं भ० ६०० ६०० ६०० ६००-७ फार पश्चिमी यमुना नहर हाईट्रोइन्वेस्ट्रिक प्रोजेक्ट” होना चाहिए।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, सीम हजारी, दिल्ली में सरकार की साल में मार्वेजनिक सूचना मेंद्या १४४-आई० ६०० सी० (पी० एन०)/६८ दिनांक ३०-८-१९६८, स० २३३-आई० ६०० सी० (पी० एन०)/६८, दिनांक, २४-१०-१९६८, स० १३२-आई० ६०० सी० (पी० एन०)/७१ दिनांक ५-१०-७१, स० ७४-आई० ६०० सी० (पी० एन०) ३१-५-७४ और दिनांक स० १०३-आई० ६०० सी० (पी० एन०)/७६, दिनांक १२-१०-७८ में यथा निर्धारित तरीके में जमा होना चाहिए।

6(3) भारत सरकार विन भंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी माप किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर संबद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अस्तिरिक्त धनराशि में बाजारों के निमित्त भेजेगा जो विन भंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मार्गी जाए। बालान के विभिन्न कालामों को भरने समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर देना चाहिए कि मार्वेजनिक सूचना स० १०३-आई० ६०० सी० (पी० एन०)/७६, दिनांक १२-१०-७६ के साथ पर्याप्त जानी वाली सार्वजनिक सूचना स० १३२-आई० ६०० सी० (पी० एन०)/७१, दिनांक ५-१०-१९७१ के पैरा-२ में निर्धारित मूल्याना और मार्वेजनिक सूचना स० ७४-आई० ६०० सी० (पी० एन०)/७४, दिनांक २१-५-७४ में भी निर्धारित सूचना बालान के कालाम “धन परेण्य और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण व्यौरे” में निरपवाद रूप से निविष्ट किए गए हैं। बालान बालान में निम्नलिखित व्यौरे निरपवाद स्थान से प्रस्तुत करने चाहिए:—

(क) विन भंत्रालय के प्राधिकार पत्र स० और दिनांक

(ब) येस मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निकेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी संभरक की भुगतान करने की नियम

उसके पश्चात् सी० ५० ए० ६० ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकारण व या संदर्भ देने हुए और बोजक नया पोत परिवहन दस्तावेजों को मलमन करने हुए खजाना बालान इयाया जमा करने का साथ देने हुए गंजीकून दाक द्वारा सी० ५० ए० ६० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:— भारत में प्रायतक के बैंक को यह मुनिष्चय करना चाहिए कि यह का निकेप भारतीय बैंक, टोकियो में अवायारी की मुद्रना और अपरिवर्तनीय गोल लकड़ान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर तिरापवाव स्पष्ट में किया जाना चाहिए और यह कि इसके तकाल बाद सी० ५० ए० ६० विन्त मंत्रालय (प्रार्थक कार्य विभाग) नई दिल्ली को भूषित कर दिया जायगा।

6(4) भारत में संबंध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर इयाया निकेपों की धनराशि का पृष्ठकूल करना चाहिए और अपेक्षित “एस” प्रपत्र भारतीय वित्रवं बैंक आफ हृषिया बंदर्ह को भेजना चाहिए।

खण्ड 8—विविध अवस्थाएँ :

8(1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पोनलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और ऐप धनराशि के बारे में सावधन छोड़ने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेकर एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, प्रार्थक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, य० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संमद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

8(2) संभरकों को विशेष गति के बारे में प्रधिसूचित करना —

लाइसेंसधारी का आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबन्धों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने से जाने में संभरक पर प्रभाव डालती हों।

8(3) विवाद:

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा नो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तराधार्यत नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली गति अनुबंध 3 में “भुगतान की गति” के अन्तर्गत घट्टी तरह से स्पष्ट कर देना चाहिए। गतिवाद की गति में विवाद के निपटान से संबंध अवस्थाएं जामिल होनी चाहिए।

8(4) भविष्य अनुदेश:

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ आड़े होने वाले किसी मामने या मधी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येत केंटिट ममझोते (पृष्ठ बन्धु मद्दायना) सं० आई० डी० पी० 7 के अधीन मधी आपार्टमेंट को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर आरो किए गए नियंत्रणों, अनुदेशों, या भ्रादेशों का लाइसेंस धारी को सुरक्षा पालन करना होगा।

8(5) अनिकम्पणा या उल्लंघन:

उपर्युक्त बांधों में स्थिर की गई गति के अनिकम्पण या उल्लंघन करने वाले आयात-निर्यात (नियंत्रण) प्रधिनियम के अधीन उचित कारंवाई भी जाएगी।

8(6) अनुबन्धों की सूची—

1. अनुबन्ध	1	पात्र आंत वेशों की सूची
2. अनुबन्ध	2	प्रधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग शर्तें
3. अनुबन्ध	3	प्रधिकार-पत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4. अनुबन्ध	4	प्रधिकार पत्र का प्रपत्र
5. अनुबन्ध	5	मार्ग-पत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए लागू)
6. अनुबन्ध	6	मार्ग-पत्र का प्रपत्र (मेवाओं के लिए लागू)

अनुबन्ध 1

पात्र आंत वेशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र :

(क-1) ओ० पी० ई० सी० में मिश्र विकासशील देश :

(ख) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र :

(ख-1) नान-ओ० पी० ई० सी० विकासशील देश :

1. अफ़्रीका, उत्तरी भारत :

मिथ

मोरोको

सुनीशिया

2. अफ़्रीका, विल्यानी भारत :

अंगोला

ओस्त्रिया

बान्डी

कैमरून

कैप बर्डी द्वीप समूह

कैरोलियन अफ़्रीका गणनाल

जात्र

कमोरो द्वीप समूह

इयोगिया

जामिया

जाना

गिनी

आङ्गोली कोस्ट

कीनिया

लेसोथो

लाइबेरिया

मालायासी गणराज्य

मालावी

माली

मारिंगोनिया मारीशस

मूजास्त्रीक

माइग्रा

पुर्नगानी गिनी

प्रियुनियन

रांडोमिया

रवान्डा

सेट हैविना और डेम (2)

माप्रोटोम और प्रिन्साइट

सेनेगल

सेजिलिज

सियरा लिंगोन

सोमालिया

सूडान

स्वाझी लैण्ड

टेरी आपन्त और इत्यास

टोगो

युगान्डा

तंजानिया गणतंत्र संघ

अपर बोल्टा

जाहरे गणतंत्र

जाम्बिया

3. अफ्रीका उत्तरी ओर केन्द्रीय :

बेल्जियम

बारबोडोज

बेलाइज

बर्गुड़ि

कोस्टारिका

कम्बोडा

डोमिनिकल गणतंत्र

एस साल्वेडोर

गुआडलौप

खाइमाला

हेटी

होन्दुरस

जेमेकानी

माटिनिक

मैक्रिसको

मीदरलैड एनटिक्षीज

निकारागुया

पनामा

सेल्वियरों और मिक्रोनीज़

ट्रिनिडाड और टोबूगो

वैस्ट इङ्लीज (शास्त्रा) एन आई ई.

(क) सम्बन्धित राज्य (1)¹

(ख) आश्रित (2)

4. दक्षिणी अमेरीका :

अर्जेन्टीना

बालिविया

ब्राजील

चिली

(1) पहले स्थेनी गिनी का प्रदेश, फरतेन्डो पी द्वीप सहित

(2) निम्नलिखित ईपों महिस.—

प्रसेन्यन, डिस्ट्रिक्ट डा इन एफसोमिक्सिल, नाइट्रिन गक

कोलम्बिया

फलकलेंड द्वीप समूह

फ्रांसीसी गिनी

गुयाना

पाराग्वे

पीरू

बुरिनास

उरुग्वे

5. भूम्य पूर्वी एशिया :

बहरीन

हजराइल

जोड़ेन

सेबनान

ओमन

सिरिबाई अरब गणतंत्र

यनाइटेड अरब अमिरात

यमन अरब गणतंत्र (3)

यमन जनबादी डी० आर० (4)

6. दक्षिणी एशिया :

अक्टानिन्हान

बांगला देश

भूटान

बर्मा

भारत

भास्त्रीय

नेपाल

पाकिस्तान

श्री संका

7. दक्षिण पूर्वी एशिया :

बहस्ती

हांगकांग

क्रमेर गणतंत्र

कोरिया गणसंघ

लाओस

गकांडो

बलेश्विया

फिलिपीन

सिगापुर

नाइजीरिया

वाहलू

निमीर

वियतनाम गणतंत्र

वियतनाम जनबादी गणतंत्र

(3) मुख्य द्वीप यमूह, अख्ता, गोनाहरे युराकायों शाहा, सेल्वियरों नाइट्रिन (विश्व भाग)

8. ओसिनिया :

कोक दीप समूह

फिरी

गिल्बर्ट और हनाइस दीप

फ्रासिसो पोनिनेशिया (5)

नीर

लूकोलेडेनिया

स्कूडेशियल (फ्रि शीर के)

हिमू

वैभिन्निक दीप समूह [संयुक्त शब्द (6)]

पापुआ न्यू गिनी

सोलानन दीप समूह (फ्रि)

ट्रोंगों

वालिस और कुतुना

पश्चिमी समाझो

9. मूरोप :

साइप्रस

किक्कल्टर

प्रीक

माल्टा

म्पेन

सुकों

बृगोल्लासिया

(1) बूल्य दीप एन्टिग्वा, डोलिनिका, मेनेडा, सेन्ट किल्डा
(मेस्ट किस्टोकी) नेविल फ्रांसिला, सेन्ट लुसिया और सेन्ट किलेन्ट
(2) मेन आइलैंड, मोन्टेसरत, सेनान, तुके और काउकोल और लिटिश बर्गिन आइलैंड समूह ।
(3) अजमान, बदल, फूजाइरह, रास अब सीमाह शारहजाह और उम अबल कैबेने
(4) अबन और विभिन्न सुखननत और असीरान ज़हिन ।
(5) सोलायटी आइलैंड्स समूह (नाहिरी सहित) को सामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह, दुआमीट जाम्यकर सूप और भारिसन दीप समूह
(6) वैभिन्निक दीप समूह का इस्ट प्रदेश कारोलीन दीप समूह, मार्शल दीप समूह और मेनिना दीप समूह (गाम की छोड़कर)

(क-2) —ओ० पी० ई० सी० के लदस्य का सहयोगी नेता :-

अर्लीरिया

बोलिबिया

लीबियाई अरब गणराज्य

गेब्रात

नाइजीरिया

इंडोनेशीर

बेन्जुएला

ईरान

ईराक

कुवैत

कातार

साउथी अरब

अबुधाबी

इर्वानेशिया

समुद्रधर्म 2

जहां के अधिन अधिकारित करने के लिए भार्य दर्शन

विषय सूची की नालिका

प्रत्यक्षेत्र संघर्ष

प्राप्ति

प्रनुच्छेद 1

गामान्य

खण्ड 1. 01

प्रस्तावना

खण्ड 1. 02

प्रौपचारिक खुल अन्तर्राष्ट्रीय निविवा करने से प्रिय विद्यार्थि

खण्ड 1. 03

संविदाश्रों की किस्म और आकार विज्ञापन और इससे पूर्व की शर्तें

खण्ड 2. 01

विज्ञापन

खण्ड 2. 02

बोली लगाने से पूर्व की शर्तें

प्रत्यक्षेद 3

बोली लगाने वाले दस्तावेज

खण्ड 3. 01

निधि के लिए संबंध

खण्ड 3. 02

बोली बाण्ड अथवा गारंटीयां

खण्ड 3. 03

संकिश की शर्तें

खण्ड 3. 04

विशिष्टिकरणों का स्पष्टीकरण

खण्ड 3. 05

मापदण्ड

खण्ड 3. 06

ब्राण्ड नामों का उपयोग

खण्ड 3. 07

संविदाश्रों के अन्तर्गत अध्य

खण्ड 3. 08

बोलियों का मूल्य

खण्ड 3. 09

संविदा मूल्य

खण्ड 3. 10

मूल्य सम्बंध धाराएं

खण्ड 3. 11

प्रियम भुगतान

खण्ड 3. 12

गारंटीयों निष्पादन बांड और रोक रखा गया धन

खण्ड 3. 13

बीमा

खण्ड 3. 14

चुकाई गई क्षति और बोनस धाराएं

खण्ड 3. 15

बाठ्यकर स्थितियां (फोर्स मेज्यूर)

खण्ड 3. 16

भाषा की व्याख्या

खण्ड 3. 17

विवादों का निपटारा

प्रत्यक्षेद 4

बोली बोलना, मूल्यांकन और संविदा प्रदान करना बोली आमत्रिन करने और बोली लगाने के बीच का समय

खण्ड 4. 02

बोलियों की किया विधि

खण्ड 4. 03

बोलियों का स्पष्टीकरण या परिवर्तन

खण्ड 4. 04

किसाविधि गोपनीय रखना

खण्ड 4. 05

बोलियों का परीक्षण

खण्ड 4. 06

बोलियों के पूर्व की शर्तें

खण्ड 4. 07

बोलियों का मूल्यांकन तथा तुलना

खण्ड 4. 08

बोलियों को रह करना

खण्ड 4. 09

संविदा प्रदान करना

प्रत्यक्षित ५	सत्ताहकारों के उपयोग के लिए मार्ग वर्णन
खण्ड १. ०१	गवाहकारों की स्वत्त्वता
खण्ड १. ०२	मताहकारों का व्यवहार
संलग्न अस्तु पात्र स्त्री देश	

अनुच्छेद १

शृण के अस्तर्गत वाल प्राप्त करने के लिए मार्ग वर्णन

मामात्य

खण्ड १. ०१ प्रस्तावना :

(क) ये निर्देशन बिल्कु उन नियमों को बताते हैं जो कि विदेशी आधिक महायोग निधि (इनके बाद "निधि" कहता है) उस परियोजना के विकास के लिए माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मामात्य लागू करती है जिसके लिए निधि प्राप्त शृण द्वारा पुर्ण रूप में अथवा आधिक रूप से विश्व प्रदान करती है।

(ख) निधि के शृण की रकम की मितश्चयता वक्तव्या और उन देशों के बीच बिना भेदभाव की भावता को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उपयोग करना होगा जो कि उपर्युक्त माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए पात्र है। (ऐसे देश इसके पश्चात् "पात्र लोग देशों" के नाम से जुड़ा हो गए हैं)। निधि यह विचार रखती है कि बहुत से मामात्यों में औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा, परियोजना के विकास के लिए माल और सेवाओं की आधिक और दक्षतापूर्ण अधिप्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। अतः निधि अपने शृणों से साझारणतः ज्ञेश्वर करता है कि वह औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के प्राप्त्यम से मात्र तथा सेवाओं को प्राप्त करें।

(ग) निधि द्वारा वित्तान की गई किसी विशेष परियोजना के लिए इन निर्देशन बिल्कुओं का लागू होना, बोली लगाने के दस्तावेज और अधिप्राप्ति की कियाविधि या जिस सीमा तक निधि द्वारा यह मुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षा के प्रयोग हैं कि वे इन निर्देशन बिल्कुओं के अनुरूप हैं, पात्र स्त्री देश और आपात स्त्री देश से अनुरूप आधिकारों के लिए प्राप्तवान उग्र परियोजना के लिए निधि द्वारा प्रदान किए गए शृण के विविदा मानकीय दस्तावेजों में निर्दिष्ट किए गए हैं।

(घ) किसी भी परियोजना पर माम और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए अलिम उत्तराधिक परियोजना के स्वामी पर होता है। चूंकि स्वामी प्राप्त शृणी भी होता है इसलिए इन मार्ग निर्देशन बिल्कुओं में शृणी गब्द का प्रयोग मालिक के लिए भी किया गया है। परियोजना के लिए विभिन्न विकास करने के लिए बोली लगाने वालों के विषय में शृणी के अधिकार और दायित्व शृणी द्वारा जारी किए गए थानी, दस्तावेजों द्वारा शामिल किए जाने हैं इन मार्ग निर्देशन बिल्कुओं द्वारा नहीं ये निर्देशन बिल्कु केवल शृणी और निधि के बीच क्या सम्बन्ध हैं इनमें सम्बन्धित हैं।

खण्ड १. ०२ औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से विश्व कियाविधि:—

कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा उत्तिष्ठ न डाहरे और निर्मलिष्वित मामात्यों में निधि अन्य हस्तरै तरीके अपनाएँ:—

(क) जिन मामात्यों में शृणी के पाम अपने उत्तिष्ठ का एक उचित मानकोकरण कायम रखने के लिए विष्वभन्तीय कारण हों;

(ख) जिन मामात्यों में पात्र संभरकों की संख्या सीमित हो जैसे विद्यमान उपस्कर के लिए फालतू पुर्णी की संख्या;

(ग) जिन मामात्यों में अधिप्राप्ति के लिए लगी हुई धनराशि इसी कम हो कि विदेशी परियोजना रूप से ५८८८ न.०। ॥ २६

कि अन्तर्राष्ट्र भार प्रशासकीय भार औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के साथ से महत्वपूर्ण हो।

(घ) जिन मामात्यों में उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) के अनिरिक्षित निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की वित्तविधियों को लागू करना अनुरूप समझता है या निधि ऐसी क्रिया विधि को अनुरूपक वक्तव्यता है तदाहरणार्थ प्राप्तवाकालीन अधिप्राप्ति के मामात्यों में।

उपर उल्लिखित मामात्यों में निर्मलिष्वित माल प्राप्ति का कार्यलय इस प्रकार लागू किया जाए कि वह औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा कियाविधि का पूर्ण सम्भव सीमा तक यथा उपयुक्त पालन करे।

(१) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा

(२) औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगात्मक अधिप्राप्ति

(३) एक ही संभरक सीधे ही द्वारा।

खण्ड १. ०३ संविदाओं की किसी और आकार:

संविदाएं निष्पादित वाम के लिए इकाई मूल्य के या आवेदित मात्रों के या एक मूल्य कीमती के या संविदा के विभिन्न मात्रों के लिए दोनों के समन्वय के आधार पर, प्रयाप्त किए जाने वाले माल या सेवाओं के स्वरूप के अनुसार की जा सकती है और बोली लगाने वाले इस्तावेजों में चुनी गई संविदा की किसी की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। वास्तविक भूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं हैं।

विस्तृत प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए, अलग अलग संविदाएं निकटके लिए बोलिया आमतित की जाती हैं, जब भी सुविधाजनक हो इनने बड़े आकार की होनी चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर बोलिया आकर्षित कर सके। बूली और, यदि तकनीकी और प्रशासकीय रूप से किसी परियोजना को संविदाओं से विभक्त करना सम्भव है और इस प्रकार किया दुमा विभाजन लाभकारी होने की सम्भावना है तो विस्तृत रूप से औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निधि की अनुमति प्रदान करने के लिए परियोजना इस प्रकार विभाजित की जाएगी।

इंजीनियरिंग उपस्कर और निमिति के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल संविदा (टर्नकी संविदाएं) यदि शृणी देश के लिए तकनीकी और आधिक लाभ प्रदान करें तो स्वीकार्य है।

अनुच्छेद २

विज्ञापन और पूर्व अहतार्थ

खण्ड २. ०१ विज्ञापन :

औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निधि के प्रधीन सभी संविदाएं बोली आमतित करने के लिए शृणी देश में सामात्य प्रचार के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित होनी चाहिए। विज्ञापन के लिए बोली आमतित करने की प्रक्रिया पात्र स्त्री देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए।

खण्ड २. ०२ बोली लगाने वालों की पूर्व अहतार्थ:

जिन मामात्यों में निधि बोली लगाने वालों की पूर्व अहतार्थी को आधारित समझनी है, उसमें निधि बोली लगाने से पूर्व की शर्तों को मान्यता प्रदान कर सकता है। यह निर्मलिष्वित बोली को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन की जानी चाहिए:—

(१) प्रथमेक पार्टी का ममात वार्ष में अनुभव और भूमिकालीन विष्वादन,

(२) कमेचारीगण, उपस्कर और संयंत्र के सम्बन्ध में उसकी सामर्थ्य, और

(3) उपरी आर्थिक स्थिति ।

पाव गमसे जाने के लिए हठआ चलने वाले संविदाकारों को संभिल विशिष्टिकरण उगलबद्ध कराए जाएँगे । यदि पूर्व प्रहृताएं प्रयाग की गई हीं तो उन राखी पाठियों को बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी औ पात्र पाई गई हैं ।

अनुच्छेद 3

बोली के वस्तावेज

खण्ड 3.01 निधि का मंत्रम् :

बोली लगाने वाले वस्तावेज निम्नलिखित भाषा में होने चाहिए :—

“..... (ऋणी का नाम) ने विदेशी आर्थिक समूहों निधि से एक ऋण येन मे (परियोजना का नाम) की सीमित के मध्ये ने प्राप्त किया है (प्रथमा उपयुक्त मामलों में प्राप्तेन किया है) ।”

खण्ड 3.02 बोली बाण और गारंटीयों :

बोली बाण या बोली की गारंटीयों साथारण आवश्यकताएं हैं लेकिन इनपोइटना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उक्त बोर्नीकार अतोत्साह हो जाए । बोली बुलने के पश्चात् ऐसे ही सम्भव हो बोली बाण अथवा गारंटीयों प्रमाणन बोलीकारों को दिला कर दी जाएँ ।

खण्ड 3.03 संविदा की शर्तें :

संविदा के प्रशासन और उपके अधीन किए गए किसी परिवर्तनमें दी गई संविदा की शर्तों में अणी और ठेकेदार या संभरक के अधिकार और दायित्व और यदि अणी दाग कोई अन्तिम नियुक्त किया गया है तो उपके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए । संविदा की परम्परागत मामला शर्तें जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निर्देशन विद्युतों में किया गया है कि अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शर्तों को सीमित करना चाहिए ।

खण्ड 3.04 विशिष्टिकरणों की स्पष्टता :

जहाँ तक संभव हो पूर्ण किए जाने वाले कार्य संभारित किए जाने वाले माल और सेवाओं और मुद्रादो या संस्थापन के स्थान की विशिष्टिकरणों में स्पष्ट और यथार्थ रूप से घोषित करना चाहिए । आलेख विशिष्टिकरणों के मूल विषय के अनुसार होने चाहिए जहाँ पर ऐसा नहीं होगा वहाँ पर मूल विषय ही प्रधान रहेगा । विशिष्टिकरणों में उन मुद्दों तथा या आधारों की पहचान होनी चाहिए जिनके बोलियों का मूल्यांकन करने समय और उनकी तुलना करने समय व्याप्ति में राहा जाएगा इसके प्रतिशिक्त कोई प्रथा सूचना, स्वल्पीकरण, विशिष्टिकरणों में हृदृश गलतियों को ठीक करना अथवा उनमें परिवर्तन करने के गतिविधि में उन सभी को तुरन्त सूचना भेजी जाएगी जिन्होंने मूल बोली वस्तावेजों के लिए प्रावेदन किया है । बोली के दामंकण में पात्र स्वोत रेख निर्धित होने चाहिए और अपार स्वोत देशों से प्रत्येक आधारों के लिए यदि कोई प्रावधान हो तो वह भी निर्विष्ट होना चाहिए । जिन मामलों में निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा (देखिए खण्ड 1.02) से सिव्र त्रिवादियों के लिए सहमत हो गई है उनको औपकर विशिष्टिकरण का इमर्गे इस प्रकार उल्लेख होना चाहिए जिससे अधिक ते अधिक अन्वरणीय बोली लगाने वालों को अनुमति और प्रोत्साहन मिले ।

खण्ड 3.05 मानवण :

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल हैं तो विशिष्टिकरण में यह वर्णित जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड की पूरा करने वाली पर्याप्तताएं जो मापदण्डों की कोटि के बगवर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती है उन्हें भी स्वीकार कर दिया जाएगा ।

खण्ड 3.06 बाण शर्तों का प्रयोग :

यदि विशेष प्रकार के कालत्रु पुजों की प्रायशकना है या यह निष्ठय किया गया है कि कुछ खान आवश्यक विशेषशर्तों को बढ़ाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिप्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्ठावन शर्तों पर आधारित होने चाहिए और उन्हें एक केवल बाण शर्त, मूली संदर्भ या विशेष विनियोगों के उत्पादों की निष्ठारूप करना चाहिए बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पर्याप्तताएं के प्रनालीयों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विवेषता मिलती-जुलती है और कम भी कम उन विशिष्टिकरण के बायार विश्वावन और गृह उनमें हैं ।

खण्ड 3.07 संविदाओं के अन्तर्गत खावें :

चंकि निधि के ऋण का उपयोग पात्र सौत देशों के क्षेत्र में उत्साहित माल के लिए अपात्र बोल देशों से अनुमति आवश्यक है तो यह और पात्र सौत देशों में भेजी गई सेवाओं के लिए किए जाने वाले व्याप में विलदान करने तक ही सीमित है इतनलिए संविदा के अन्तर्गत बोली वस्तावेजों में ठेकेदार अपेक्षा संभरक को अपने व्यवस्थापन सुनाए रखने चाहिए या अपने विवरण पत्रों या बीजियों में अपात्र बोल देशों में लिए गए वह बोल कोध करना चाहिए । जिन माल और सेवाओं के लिए निधि विलदान करती है उनके भीगोलिक मूल उदागम और उनके प्रमुख संभरकों से संबंधित सूचना की आवश्यकता निधि को सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए होती है । ठेकेदार अपेक्षा संभरकों को बोली वस्तावेजों में आवश्यक सूचना भेजनी चाहिए ।

खण्ड 3.08 बोलियों की कीमत लगाना :

चंकि निधि ऋण जापान येन में वर्णित किया गया है, बोली का मूल्य जापान येन में दरवाजा जाना चाहिए लेकिन बोली मूल्य का वह भाग जिसकी बोली लगाने वाला अणी के देश में बद्ध करना चाहता है उसका अणी की मुद्रा में किया जाना चाहिए ।

खण्ड 3.09 संविदा की कीमत :

संविदा कीमत जापान येन में वर्ताई जानी चाहिए व्यर्थों कि संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार अणी के देश में बद्ध करेगा अणी की मुद्रा में रखया जाना चाहिए ।

खण्ड 3.10 मूल्य समंजन कठिकारें :

बोली वस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों में वृद्धि भी आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है । यदि संविदा के प्रमुख सामग्र अवयवों अर्थात् अम और महत्वपूर्ण नामधी की कीमतों में कोई परिवर्तन होता हो तो उपयुक्त मामलों में संविदा की कीमतों में समंजन (उत्तार चडाव) के लिए व्यवस्था होनी चाहिए ।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूख बोली वस्तावेजों में साफ-साफ परिभ्रषित होना चाहिए ताकि वहीं प्रावधान भेजी बोलियों में लागू किया जा सके माल की समानी के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन मिलित कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए ।

एक व्यर्थ के अन्वर सुनाएं किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की व्यवस्था प्राप्त नहीं होनी चाहिए । ये माल 'मिर्देशन विन्दु' उन विभिन्न उपायों के परिवर्त्य का आधार नहीं करती है जिनके द्वारा संविदा मूल्य मंजित किया जा सके ।

खण्ड 3.11 अप्रिम भूगतान :

व्यर्थ भूगतान के लिए संविदा के सम्मान एवं अप्रिम रूप से किए गए कुल भूगतान का प्रतिशत उचित होना चाहिए । अर्थ दिए जाने वाले

प्रथम छन जैसे काम में आने वाले माल की साईट पर सुपुर्दीनी के लिए भी बोली दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए।

खंड 3.12 गारस्टी निष्पादन बोर्ड और रोकी रखी गई धनराशि :

नागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारस्टी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक वह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेगा। यह जमानत या तो बैंक गारस्टी द्वारा अधिकार निष्पादन बोर्ड द्वारा यी जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की किसी और परियोग के अनुसार भिन्न-भिन्न होती, लेकिन टेकेवार में कभी पाए जाने के मामले में अणी को मुक्त अधिकार निष्पादन करने के लिए पर्याप्त होती चाहिए। उचित जमानती अधिकार को पूरा करने के लिए संविदा को पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में बद्धि यी जानी चाहिए। गारस्टी या अपेक्षित बोर्ड की धनराशि को बोली दस्तावेजों में निरूपित किया जाना चाहिए।

माल की सफ्टार्क के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह बांधनीय होता कि बैंक गारस्टी अधिकार बोर्ड की अपेक्षा गारस्टी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोकी रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए राशें बोली दस्तावेज में निर्विष्ट होना चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारस्टी अधिकार बोर्ड चुना जाता है तो यह केवल नाममात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

खंड 3.13 बीमा :

सफल बोलीकार द्वारा यी जाने वाली बीमे की किसी का बोली दस्तावेजों में संशेष में वर्णन होना चाहिए।

खंड 3.14 चुकाई जाने वाली शक्ति और बीमास प्रावधान :—

अणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दीनी में देर होने के कारण कालतू खर्च, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली शक्ति से संबंधित प्रावधान शामिल होना चाहिए। टेकेवार द्वारा संविदा में निर्विष्ट समय पर अधिक उमसे पहले नागरिक निष्पादन कार्य पूरा करने के लिए और जब कि समर्प से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य अणी को साभकारी हो तो टेकेवार की बोनस देने की भी अवस्था की जाए।

खंड 3.15 बाध्यकारी परिवर्तन :

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे प्रान्तुर्धित करने हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के प्रान्तर्गत पार्टी द्वारा अपने वायितों को न पूरा करना उस हालत में एक छूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी बूक विवरण स्थितियों (फौस मेजोर) के कालस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है)

खंड 3.16 भाषा की व्याख्या :

बोली दस्तावेज अंगेजी में तैयार किए जाने चाहिए। यदि बोली दस्तावेजों में भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंगेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

खंड 3.17 शगड़ों का निपटान :

शगड़ों के निपटान में संबंधित अवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह बांधनीय है कि अवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापिण्य मंडल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" पर आधारित होने चाहिए।

प्रभुचक्षेत्र-4

बोली बोलना, मूल्यांकन और टेका देना

खंड 4.01 बोलियों के आमंत्रण और प्रस्तुत करने के बीच का समय :

बोली तैयार करने के लिए इनुमित समय अधिकतर संविदा की महत्वता और पैकीजिंग पर निर्भर करेगा। साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 45 विनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए। जहां पर नागरिक निष्पादन कार्य अधिक है, वहां पर प्रस्तावित बोलीकारों को अपनी बोलियों प्रस्तुत करने से पहले ल्यान पर भली-भाली वेळ-भाल करने के लिए आम तौर पर कम से गम 90 दिन दिए जाने चाहिए। किसी अनुभित समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों की ध्यान में रखने हुए होना चाहिए।

खंड 4.02 बोली बोलने की कियाविधि :

बोलियों की अनियन्त्रित वापती के लिए और बोली-बोलने के लिये लियि, समय और स्थान की बीच: आमंत्रण में धोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियों निर्धारित समय पर बुले आम बोलनी चाहिए। इस समय के बावजूद प्राप्त होनी वाली बोलियों की विना बोले ही सोचा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वकालिक बोलियों की कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

खंड 4.03 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन:

बोली बुलने के पश्चात किसी भी बोली बोलने के उत्तरी बोली में परिवर्तन करने की प्रामुख्य नहीं ही जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़े। अणी किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है लेकिन बोलीकार की उसकी बोली के धारात्मक एवं मूल परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

खंड 4.04 गुप्त रखी जाने वाली क्रियाविधि :

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली के बुलने के बावजूद बोली से संबंधित मिरीकाना, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और लियि से संबंधित सिफारियों के बारे में भी उस ध्येत को जो इन क्रियाविधियों से आधारित अधिकार के प्रत्येक रूप से संबंधित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को जोखित नहीं कर दिया जाता है।

खंड 4.05 बोलियों की जाँच :

बोलियों के बुलने के बावजूद कानून का सुनिक्षण कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिया दी गई है, क्या बोली दस्तावेज विकृत बोलियों के अनुसार है, क्या आवश्यक जमानतों की अवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधित छूलाकरित है और क्या बोलियों सामान्यतया अव्याध रूप से सही हैं? यदि बोलियों मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं हैं या उसमें अस्वीकृत गते हैं या अव्याध रूप में बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें प्रस्तीकृत किया जाना चाहिए। इसके बावजूद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

खंड 4.06 बोलीकारों की पूर्व योग्यताएँ :

पूर्व भांतिकारों की अनुपस्थिति में आपातक को चाहिए कि वह हम बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास संबंध संविदा को प्रभावी रूप से बलाने के लिए क्षमता है और इन कामों का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अलीकार कर दिया जाना चाहिए।

खण्ड 4. 07 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान :

बोलियों का मूल्यांकन बोली वस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिए। नियतीय गलतियों के लिए समंजित बोली की कीमत के अनुरूप अन्य बातों द्वारा निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्यकुशलता एवं क्षमता या फालत् पूर्जों की उपलब्धता और प्रत्यावित निर्माण कार्य नीरों की विधिवालीयता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहाँ तक नीरों ये बातें बोली वस्तावेजों में विविधिकृत मानदण्ड के अनुसार एवं ऐसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समंजित कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राएँ जिनमें मूल्य आंका जाता है बोली स्वीकृत होने पर उन्हीं द्वारा मुग्नान किया जाएगा और सभी बोलियों की तुलना अपनी द्वारा जूनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली वस्तावेजों में भी होना चाहिए। ऐसे मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनियम की वर सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशित विकल्प वर्तों पर होनी चाहिए और जब तक नियम होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियों द्वारा होने के दिन तक उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के विर्णव अधिसूचित करते समय विनियम की वर उपयोग में लाई जानी चाहिए।

बोली की मूल्यांकन और मिलान की रिपोर्ट जिसमें विशेष कारण निर्धारित किए गए हैं जिन पर न्यूनतम मूल्यांकित बोली का निर्धारण आधारित है अर्थी या उसके सलाहकारों द्वारा तैयार की जानी चाहिए:

खण्ड 4. 08 बोलियों को अस्वीकृत करना :

बोली वस्तावेजों में सामान्यता यह व्यवस्था की गई है कि अर्थी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकृत करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रत्योजनार्थ उसी विधिविकरण पर नई बोलियों प्रारंभित नहीं की जानी चाहिए। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहाँ न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमति कीमत से प्रधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अस्वीकृत करने के लिए भी तब अधिकार्य देने चाहिए जहाँ (क) बोलियों, बोली वस्तावेज के आधार के अनुसार नहीं हैं या (ख) अनुसूत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो अर्थी की चाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों की पुरारीका करे जिससे अस्वीकृति सिद्ध की गई है और या तो विधिविकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिवर्तन पर (या बोलियों के लिए न्यून आमंत्रण में मारी गई पर्यावरणीयों की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करें। विशेष स्थितियों में नियम पर विचार करने के बावजूद अर्थी संतोषजनक संविधान प्राप्त करने के लिए किती एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकार के साथ सीधा कर सकता है।

खण्ड 4. 09 संविदा का नियम :

संविदा का नियम उस बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर नियमित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए वह आवश्यक नहीं होता चाहिए कि वह नियम की एक शर्त के रूप में विधिविकरण में निर्धारित पर्यावरणीयों के लिए या अपनी बोली को परियोगित करने के लिए जिम्मेदारी ले।

बोलियों का विश्लेषण करने के पश्चात् बोलियों के विश्लेषण की प्रतियों और नियम के लिए प्रस्ताव ऐसे प्रस्तावों के लिए कारणों सहित नियम के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

ग्रन्तुक्षेद-5

सलाहकारों के उपयोग के लिए सारंदर्शन

खण्ड 5. 01 सलाहकारों की स्वतन्त्रता :

नियम के अन्तर्गत परियोजना के वित्तवान के संबंध में नियुक्त की गई सलाहकार पार्टियों इस दृष्टिकोण से स्वतंत्र होंगी कि उनकी सलाह और आनेक विधिविकरण और उनके द्वारा बनाए गए नियिका वस्तावेज राष्ट्रीय, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक पक्षपात से मुक्त हैं।

सलाहकार इन्जीनियर जो कि ठेकेवारों अथवा विनियमण पार्टियों से मिले हुए हैं केवल उभी उपयोग में लाए जा सकेंगे जबकि स्वयं और उनके साथी एक ही परियोजना पर किसी भी अन्य क्षमता से कार्य के लिए प्रयोग विधित किए जाएंगे। सलाहकार इन्जीनियरों के मामले में जो विविधताओं के साथ लगे हुए हैं और सलाहकार सेवाएँ प्रवान करते हैं तो वह सुनिश्चय करने के लिए ही व्याप नहीं रखा जाएगा कि वह कंपनी जिससे सलाहकार संबंधित है परियोजना के किसी भी भाग पर भवित्व में बोली धोने के लिए न केवल अप्रयोग विधित कर दी जाएगी बल्कि वे विधिविकरण निष्पत् होंगे और उनका प्रतियोगिता के आधार पर पालन किया जाएगा।

खण्ड 5. 02 सलाहकारों का चयन :

सलाहकार पार्टियों के चयन के लिए शौपचारिक प्रतियोगात्मक बोली विद्याविधियों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, चयन के दौरान अर्थी प्रत्याशित पार्टियों की उचित संख्या पर विचार करेगा जिसमें नियम द्वारा अधिकृति पार्टियों भी शामिल होंगी, जिनमें पाल स्रोत वेशों द्वारा उचित तथा स्वतंत्र सेवाएँ प्रवान करने की संभावना हो सकती है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण कम से कम तीन पार्टियों तक बढ़ाया जा सकेगा। प्राप्त होने पर प्रस्तावों की पहले गुणात्मक आधार पर तुलना की जानी चाहिए अर्थात् प्रोजेक्ट बनाने के संबंध में, अनुसूचियां, नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का अनुभव और क्षमताएँ, दिए गए कार्य के लिए सब से योग्य समझी गई पार्टियों की अप्रयोग। पार्टियों के चयन के पर्यावरण पूर्ण विर्णव पर वृद्धिने के लिए ग्रामतीवीकरण की जानी चाहिए। नियम द्वारा परियोजना की तैयारी और पर्यवेक्षण के लिए की गई सहायता के लिए अर्थी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रथमा पहले ही नियुक्त किए गए सलाहकारों के चयन के अनुमोदन का अधिकार नियम को प्राप्त है।

ग्रन्तुबन्ध-3

प्राधिकार पर जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र

संख्या विनाक
सेवा में,

सहायता देखा तथा देखा परीक्षा विषयक
वित्त मंत्रालय,
आधिकार्य विभाग,
यू.सी.ओ. और विलिंग, प्रथम मंत्रिल,
पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय:- 1979-80 के लिए येन फ्रैंडिंग सं० अर्थी डी-पी-७ (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत जापान से का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन फ्रैंडिंग अर्थी डी-पी-७ (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत से

कि के आयात के सम्बन्ध में
..... (वैक का नाम) जो
कि वही हीना चाहिए जो नीचे (४) में सम्बद्ध समुद्रपार संभरक के
नाम से साथ पत्र खोलने के लिए दिया गया है की प्राधिकार पत्र जारी
करने के लिए हम आपको निम्नलिखित और प्रस्तुत करते हैं:—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात साइंसेस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख
जिस तरफ दैध है।
- (ग) प्राप्ति के नरीके क्या वह सीधे क्या या
ओपेचारिक छाले अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके
मामले में यदि कोई कारण हो सो कारण सहित वह संकेतित
होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त स्थूनतम
तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण।
- (ङ) माल का उद्घाटन देश
- (च) यदि कोई हो तो पात्र से इतर स्रोत देशों से आयातित संघटकों
का प्रतिशत।
- (छ) संविदा का कुल जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में)।
- (ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि
(येन में)
- (झ) वास्तविक जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिए
प्राधिकार पत्र मांगा गया है।
- (ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं
दिनांक
- (ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता:—

 - (१) राष्ट्रिकता।
 - (२) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए शेयरों की
प्रतिशत।
 - (३) प्रतिविधि की राष्ट्रिकता और/या संभरक का निवास
स्थान।
 - (४) उन निवेशकों का प्रतिशत जो पात्र स्रोत देशों के
राष्ट्रिक हैं।

- (ठ) वे भुगतान रात्रे और संभावित तिथि जिनको संविदा के अंतर्गत
भुगतान देय होंगे।
- (इ) सुपुर्वी को पूर्ण करने की प्रत्याधित तिथि।
- (ड) भारतीय बैंक टोकियों को भुगतान करने समय दिए जाने वाले
दस्तावेज।
- (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दियाँ दूए)।
- (ण) पोतलदाता अनुबेश वाहनान्तरण/पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी
गई है या नहीं। निविष्ट कीजिए।
- (त) भारत में आयातक बैंक का नाम और पता।
- (थ) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी
गई है और जापानी प्राधिकारियों को प्रतिसूचित कर दी
गई है, यदि हो तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, दिनांक और
गूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके धंतीत
शो.०५००५०५०५० की इसे प्रतिसूचित किया गया है।

अनुबंध-4

(प्राधिकार-पत्र का प्रपत्र)

संख्या एफ
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
नहीं दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक द्वारा इण्डिया,
टोकियो शाखा
टोकियो (जापान)

विषय:—ये न श्रेइट (परियोजना सहायता) अद्य करार संख्या शार्ट डी
पी-७ के अधीन आयात साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार-
पत्र जारी करना।

प्रिय भ्रष्टाचार,

आपके बैंक के साथ २३-३-१९८० को किए गए समझौते की शर्तों के
अनुसार आपको एतद्वारा पथा संस्थान द्वारे के अनुसार सर्वश्री.....
..... के नाम में येन धन-
राशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया
जाता है।

आपके बैंक द्वारा लिए गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के
बैंक, शो.०५००५०५०५० भारतीय दूतावास टोकियो और हमें पूछांसित
की जाए।

साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान
आपके फ़ाउंड से किया जाएगा। भुगतान के बाद ओर्इसीएफ को आवश्यक
दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्णि का बाबा तदात्त करना
चाहिए।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की निधि से ओर
ओर्इसीएफ द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय के लिए
उपर्युक्त समझौते के अनुसार सारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा सीधे ही
भ्याज दिया जाएगा। बैंकों के अन्य खर्चों जिसमें साखपत्र खोलने, रख-
रखाव बरने और साखपत्रों को जारी रखने के लिए खर्च भी शामिल
हैं जोकि वे भी परकार्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित हैं और यदि
कोई हो तो, विदेशी संभरकों के बैंकों के खर्चें भी विदेशी संभरक को
ही होने पड़ेंगे और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया
जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा
सकता है। इस प्रकार के ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्णि का बाबा शो.०५०५०५०
शो.०५०५०५० में नहीं किया जा सकता।

यह प्राधिकार पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साखपत्र खोलने के
लिए है। इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के द्वारा इस प्राधिकरण के
मद्दे द्वारा गए आगे के नए साखपत्र पा भारतपत्र में बाद के संशोधनों का
ग्रन्तीकार नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकार पत्र तक वैध
रहेगा।

भारतीय,
लेखा प्राधिकारी

1. आयातक को उनके पत्र संख्या दिनांक के संदर्भ में।

2. आयातक का बैंक उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक और इण्डिया, टोकियो प्रांत से दस्तावेज प्राप्त करने पर विवेशी संभरकों को येत के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें संभरकों को भुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणता सार्वजनिक सूचना संख्या-8 आईटीसी(पी एन)/78, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिथित वर पर की जाएगी। विवेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से भारतीय बैंक को आदायनी करने की तिथि में सरकार वे लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना संख्या 46 आईटीसी (पी एन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत आर्थिक वर पर और इससे अधिक की गणता की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की वर से व्याज भी गरकारी लेखे में जमा करता होगा। व्याज दोनों दिनों के लिए दिया जायगा अत्यन्त वह तिथि जिसको विवेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में जमा रुपया निषेध किया जाता है। (इस वर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी)। यह मुनिशित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा पूल निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल में दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियाँ, या तो रिजर्व बैंक और इण्डिया, नई दिल्ली या न्यूट बैंक और इण्डिया, नई दिल्ली में जमा करनी चाहिए या इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या 184—आईटीसी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-68, संख्या 233 आईटीसी (पी एन)/68 दिनांक 24-10-68, संख्या 132 आईटीसी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971, संख्या 74 आईटीसी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और संख्या 103 आईटीसी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 की गणता की ओर दिलाया जाता है। लेकिन यीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह “के डिपोजिट एण्ड एडवांसेन्स 843 मिक्सिल डिपोजिट—डिपोजिटसंकार परचेजिम एटसेकटु कोम प्रोड परचेजिस अन्दर कैडिट/लोन एप्सीमेंट अन्डर टिटेल्ड है,” “1 विलियन येत क्रेडिट (परियोजना महायात) संख्या 7 फार 1978-80 कोम जापान क्रेडिटस कोम विगवनेंट और जापान” है।

जिन यामों में मुख्य रुपया रिजर्व बैंक और इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक और इण्डिया नई दिल्ली में सार्वजनिक सूचना संख्या-132 आईटीसी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनको चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक और इण्डिया टोकियो भाषा से ग्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्व विवरण देते हुए अपेक्षण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:-

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त भंडारण (आर्थिक कार्य विभाग)

पहली मंजिल, यू० सी० औ० बैंक इण्डिया,
संसद मार्ग, नई दिल्ली।

जिस यामों में मुख्य रुपया उपर संकेतित सार्वजनिक सूचना संख्या दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्षनी दुप्ती द्वारा प्रेषित करला है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी यामों में, जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा व्यीरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हो तो बैंकिंग खर्च, व्याज और बैंक और इण्डिया टोकियो भाषा के अन्य खर्च (विवेशी संभरक बैंकरों के खर्चों सहित) इण्डियन बैंक और बैंक और इण्डिया टोकियो भाषा द्वारा सीधे ही निपारित किए जाएंगे।

3. निदेशक, अर्ण विभाग-2, समुद्रपार आर्थिक महायोग निधि, टोकियो ग्रूपो विलिंग, 4-1, ओहुटिमेन्नी 1-कोम, वियोडान्कु, टोकियो 100, जापान।

4. भारतीय उनावास टोकियो।

5. अबर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त भंडारण आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली।

लेखा प्रधिकारी

अनुबन्ध-5

[श्रो००६०सी००एफ०एस०सी०-१ प्रपत्र]

अपरिवर्तनीय साख्यपत्र

(माल के लिए लागू)

दिनांक
सेवा में,

यह साख्यपत्र (कर्णी) और विवेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए अर्ण करार संख्या के (संभरक का नाम और पता) दिनांक के अनुभरण में जारी किया गया है।

प्रिय भ्रष्टाचार,

इस सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बैंक के पूरे मूल्य के लिए दर्शनी दुप्ती द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साख्यपत्र संख्या खोल दिया है जो (येत कह सकते हैं) कि कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित वस्तावेज के राख भेजा जाना है:-

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बैंक

मलिन शान वोर्ड, ममुरी पोतलदान विल जिसमें दिए गए आदेश का पूरा सेट ही बैंक प्रूफ़ाक्टिव एवं चिलिंग “फेट” एवं नोटिफाई

अन्य वस्तावेज जिसमें से तक नवान का अत्यापन दिया गया है (संविदा संख्या (यदि कोई हो) के मंदर्भ में भाल का संधित विवरण आर्थिक पोतलदान स्वीकृत है। बहनान्तर यदि स्वीकृत है।

पोतलदान विल जो से बाहर की सिधि नहीं होना चाहिए। आदेशी को झापट 19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी झापट और वस्तावेजों पर यह अंकन होना चाहिए। “अपरिवर्तनीय साख्यपत्र संख्या दिनांक 19 के अन्तर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ संख्या (संख्या-ए) (यदि कोई हो)”, यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।

इस प्रदाना वस्तावेज देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत यों हमारी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी झापट, प्रस्तुत करते पर और आवेशी को वस्तावेजों की सुपुर्गी पर विधिवत स्वीकृत किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप में विस्तारपूर्वक न बनाया जाए यह क्रेडिट “नूतनामे कस्टम एण्ड प्रेक्टिस फार डाकूमेन्ट्स क्रेडिट्स (1974 रिपोजिन), हस्टरनेशनल चेस्टर और कार्पर्स, प्रिलिंग नं. 290” के अधीन है।

मौद्दा करने वाले बैंक को विशेष अनुबंध :

इनमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (अलगी अयथा इसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निषादान के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इस कोडिट के अन्तर्गत भुगतान इममें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाते चाहिए। प्रारम्भिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निषादान विवरण के बजाय सापेक्षारी विवरण की आवश्यकता है।

2. और उत्तिष्ठित समझौते के अन्तीम जारी किए गए वचनबद्धता पत्र के उपनिवेशों के अनुसार विवेदी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतान के लिए प्रति पूर्ति प्राप्त करने के बाद इस ट्राफटों की धनरक्षि का मोन-सोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परेविंट करने का वचन देते हैं।

3. उपर्युक्त मर 1 में दधा उत्तिष्ठित दस्तावेज की एक प्रति और मसोदे हमें इसकी प्राप्ति के तुरंत बाब हो भेजे जाएंगे।

4. इस साथ के अन्तर्मिस बैंक के सभी वार्च तंत्रज्ञानों के लेवे के मिए हैं।

भवदेव,
(वाणिज्यिक बैंक)
द्वारा.....
(प्रारंभिक हस्ताक्षर)

MINISTR OF COMMERCE

Public Notice No. 27-ITC(PN)81

New Delhi, the 29th May, 1981

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Licensing conditions in respect of import of goods and services by the Haryana State Electricity Board under the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) Loan of Yen 4 billion.

File No. IPC/23 (15)/80-81.—The terms and conditions governing the issuance of import licence under the 4 billion Yen Credit extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Western Yamuna Canal Hydroelectric Project of the Haryana State Electricity Board as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

MISS ROMA MAZUMDAR, Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX I

Licensing conditions in Respect of Imports of Goods and services under the Yen credit of Yen Four Billion for the Implementation of the Western Yamuna Canal Hydroelectric Project of the Haryana State Electricity Board extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) of Japan.

Section I—General Conditions :

I (i) The Yen Credit of 4 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Western Yamuna Canal Hydroelectric Project of the Haryana State Electricity Board (HSEB) is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I (ii) Import Licence (s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTB/CG Committee. The value of import licence (s) issued under this credit should not exceed £ 4,440 million, (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate noticed by the Department of revenue (Customs) and prevailing on the date of

issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence (s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P.7". The first and second suffix to the licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to H.S.E.B., a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (iii) Import licence(s) can be issued only in favour of HSEB on CIF basis.

I(iv) Depending on the convenience of HSEB more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed £ 4,440 million (CIF) as specified at (i) above.

I(v) The extension of the validity of the import licence, may on application by HSEB, be granted upto 31-12-85 Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (vi) No remittance of foreign exchange will be permitted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I(vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I(viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian Licence on the overseas supplier duly signed by the letter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Order on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian Importer

from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

" Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of....."

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-85.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The broad guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure II. However, normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering and the following points should be borne in mind:—

- (a) Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.
- (b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.
- (c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II (iii) In cases where Formal Open International Tendering is not considered appropriate the Fund will accept the following alternative procedures :—

- (a) Where the importer has convincing reasons or maintaining a reasonable standardisation of his equipment.
- (b) Where the number of qualified suppliers is limited.
- (c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.
- (d) Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedure in applicable, e.g., in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement procedure may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate :

- (i) Formal Selective International Tendering .
- (ii) Informal International Competitive Procurement.
- (iii) Direct Purchases from a single supplier.

H.S.E.B. should prepare a detailed report on the evaluation and comparison of bids setting forth the specific reasons/justifications on which the lowest evaluated bid is based and submit it in triplicate alongwith bid analysis statements sheets supported by documentary evidences, if any to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section), North Block, New Delhi who will obtain the necessary approval of the same from the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF). It should be noted that purchase contracts will be notified by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) (Japan Section) to the O.E.C.F. only after obtaining the OECF approval of the report etc

II(iv) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P.7 for 1979-80 the details of which are given in Section VI below.

II(v) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(vi) Eligibility of Supplier :

The Suppliers shall be national of the eligible source countries, or juridical persons governed substantially by national of the eligible source countries, satisfying the following conditions :—

- (a) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries.
- (b) that a majority of full time directors shall be nationals of the eligible source country; and
- (c) such juridical persons have been registered in the eligible source countries.

II(vii) Declaration in Contract :

The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in(eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30 per cent) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

and

"I, the undersigned, hereby certify that(Name of company) has been incorporated and registered in(name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

II(viii) Permissible imports from non-eligible source countries.

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30 per cent) on an item-by-item basis in accordance with the following formulae;

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts.

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

- (a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 19th March, 1981 concerning the Yen Credit No. ID-P. 7 (Project Aid) for Western Yamuna Canal Hydroelectric Project of HSEB and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.
- (b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement

No. ID-P.7 dated the 18th March, 1981 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

- (c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.
- (d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in III(vii).

III(ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. in exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF :

IV(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both H.S.E.B. and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV(ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P.7 (Project Aid) for Western Yamuna Canal Hydroelectric Project of HSEB.

Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure :

V(i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, H.S.E.B. and the CAA & A will be informed of the same. Whereafter the HSEB should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, hereinafter referred to as CAA & A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure III for issue of a letter of authorisation. The CAA & A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure V (for physical imports) or Annexure VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA & A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA & A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V(iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the letter of credit, for negotiations thereunder and charges, if any, of overseas supplier's banker and interest charges payable to the Bank of India, Tokyo, for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas supplier to the date of reimbursement by the OECF shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

For the time lag between the dates of payment of the F.O.B. cost of the material by the B.O.I., Tokyo to the suppliers and the date of reimbursement by the OECF the B.O.I., Tokyo will charge interest as per the terms and conditions of the Agreement entered into by them with the Government of India (Mo Finance) on 25-3-1980 and get the same reimbursed by the Embassy of India, Tokyo. The expenditure on account of this interest payment by the Embassy of India in Japan will be recovered from the HSEB [vide Section VI(iv)] infra.

Section VI—Responsibility for rupee deposit :

VI(i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee-equivalents of the Yen payments calculated @ 9 per cent per annum for the first 30 days and @ 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Overseas Supplier to the date of actual rupee deposit, have also to be deposited alongwith the principal payment, in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas supplier and also the day on which rupee deposit is made in Government Account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/74 dated 12-10-1976.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)/74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)/76 dated the 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits/Loan Agreements" Loans from the Government of Japan—4 Billion Yen Credit No. ID-P.7 for Western Yamuna Canal Hydroelectric Project.

VI(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

VI(iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is

made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) while filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :—

- (a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.
- (b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VIII—Miscellaneous provisions :

VIII(i) Reports on the utilisation of the import licence :

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions :

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII (iii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII (iv) Future Instructions :

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P.7 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII(v) Breach or violation :

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII(vi) List of Annexures :

- Annexure—I List of eligible source countries.
- Annexure—II Broad Guidelines for Procurement.
- Annexure—III Request for issue of letter of Authority.
- Annexure—IV Form of Letter of Authority.
- Annexure—V Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports).
- Annexure—VI Form of Letters of Credit (Applicable to Services)—

ANNEXURE I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. Developing Countries and Territories :

(a1) Non-OPEC Developing Countries :

I. AFRICA, North of Sahara	St. Helena and dep. (2)
	Sao Tome and Principe
Egypt	Senegal
Morocco	Seychelles
Tunisia	Sierra Leone
	Somalia

II. AFRICA, South of Sahara

Sudan	Swaziland
Angola	Terro. Afars and Issas
Botswana	Togo
Burundi	Uganda
Cameroun	Un. Rep. of Tanzania
Cape Verde Islands	Upper Volta
Central African Rep.	Zaire Republic
Chad	Zambia
Comoro Islands	
Congo, People's Republic	
III. AMERICA, North and Cont:	
of Dahomey	

Equatorial Guinea (1)	Bahamas
Ethiopia	Barbados
Gambia	Belize
Ghana	Bermuda
Guinea	Costa Rica
Ivory Coast	Cuba
Kenya	Dominican Republic
Lesotho	El Salvador
Liberia	Guadeloupe
Malagasy Republic	Guatemala
Malawi	Haiti
Mali	Honduras
Mauritania, Mauritius	Jamaica
Mozambique	Martinique
Niger	Mexico
Portuguese Guinea	Netherlands Antilles
Reunion	Nicaragua
Rhodesia	Panama
Rwanda	St. Pierre & Miquelon
	Trinidad and Tobago

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the islands of Fernando Po.

(2) Including the following islands; Ascension, Tristan da Cunha, Inaccessible, Nightingale, Gough.

(3) Mainlands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius, St. Martin (Southern part)

**AMERICA, North & Central
(Continued)**

West Indies (Br.) n.i.e.
(a) Associated States (1)
(b) Dependencies (2)

VII. ASIA, Far East:

Brunei
Hong Kong
Khmer Republic

IV. AMERICA, South:

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

Korea, Republic of
Laos

Macao
Malaysia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam, Dem. Rep.

(a2) Member or Association Countries of OPEC:

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

V. ASIA, Middle East :

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VII. OCEANIA:

Cook Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Calendonia
New Hebrides (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

VI. ASIA, South:

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldives
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

IX. Europe

Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

- (1) Main islands : Antigue, Dominica, Grenada, St. Kitts.
(St. Caristophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent
- (2) Main islands; Montserrat, Cayman, Turks, and Caicos, and British Virgin Islands.
- (3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.
- (4) Including Aden and various sultanates and emirates.
- (5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
- (6) Trust Territory of the Pacific Islands: Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam)

OECF**The Overseas Economic Cooperation Fund****Guidelines for Procurement under****The Loan****Guidelines for Procurement under the Loan****Tables of Contents**

Article Number	Title
Article I. General	
Section 1.01 Introduction	
Section 1.02 Procedures other than Formal Open International Tendering	
Section 1.03 Type and Size of Contracts	
Article II. Advertising and Prequalification	
Section 2.01 Advertising	
Section 2.02 Prequalification of Bidders.	
Article III. Bidding Documents	
Section 3.01 References to the Fund	
Section 3.02 Bid Bonds or Guarantees	
Section 3.03 Conditions of Contract	
Section 3.04 Clarity of Specifications	
Section 3.05 Standards	
Section 3.06 Use of Brand Names	
Section 3.07 Expenditures under Contracts	
Section 3.08 Pricing of Bids	
Section 3.09 Contract Price	
Section 3.10 Price Adjustment Clauses	
Section 3.11 Advance Payments	
Section 3.12 Guarantees, Performance Bonds and Retention Money	
Section 3.13 Insurance	
Section 3.14 Liquidated Damage and Bonus Clauses	
Section 3.15 Force Majeure	
Section 3.16 Language Interpretation	
Section 3.17 Settlement of Disputes	
Article IV. Bid Opening, Evaluation and Award of Contract.	
Section 4.01 Time Interval between Invitation and Submission of Bids.	
Section 4.02 Bid Opening Procedures	

- Section 4.03 Clarification or Alteration of Bids
- Section 4.04 Procedures to be Confidential
- Section 4.05 Examination of Bids
- Section 4.06 Postqualification of Bidders.
- Section 4.07 Evaluation and Comparison of Bids
- Section 4.08 Rejection of Bids
- Section 4.09 Awards of Contract

Article V Guidelines for Use of Consultants

- Section 5.01 Independence of Consultants
- Section 5.02 Selection of Consultants

Attachment : Eligible Source Countries.

GUIDELINES FOR PROCUREMENT UNDER

THE LOAN

Article I General

Section 1.01 Introduction :

(a) These Guidelines set forth the rules which the Overseas Economic Cooperation Fund (hereinafter called "the Fund") generally applies to the procurement of goods and services for a development project which the Fund finances in whole or in part by its loan.

(b) The proceeds of the Fund's loan are required to be used with due attention to considerations of economy, efficiency and non-discrimination among countries which are eligible for procurement of the above-mentioned goods and services (such countries are hereinafter called "the eligible source countries"). The Fund considers that in most cases formal open international tendering is the best method for achieving the economical and efficient procurement of the goods and services required for the development projects it finances. The Fund therefore normally requires the borrowers to obtain goods and services through formal open international tendering.

(c) The application of these Guidelines to a particular project financed by the Fund, the extent to which bidding documents and procurement procedures are subject to review by the Fund to ensure conformity with these Guidelines, eligible source countries and provisions for permissible imports from non-eligible source countries shall be stipulated in the contractual documents for the loan extended by the Fund for that project.

(d) The ultimate responsibility for the procurement of goods and services on any projects rests with the owner of the project. Since the owner is usually also the borrower, the term borrower has been used in these Guidelines to refer to the owner as well. The rights and obligations of the borrower vis à vis bidders for goods and services to be furnished for the project are governed by the bidding documents issued by the borrower and not by these Guidelines, which are concerned only with the relationship between the borrower and the Fund.

Section 1.02. Procedures Other than Formal Open International Tendering :

There may be special circumstances in which formal open international tendering may not be appropriate and the Fund may accept alternative procedures in cases of following :

- (a) Where the borrower has convincing reasons for maintaining a reasonable standardization of his equipment.
- (b) Where the number of qualified suppliers is limited, e.g. of spare parts for existing equipment.
- (c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be

interested, or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.

(d) Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedures inapplicable for example in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement formulas may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate :

- (i) Formal Selective International Tendering
- (ii) Informal International Competitive Procurement.
- (iii) Direct Purchases from a Single Supplier.

Section 1.03. Type and Size of Contracts.

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable to the Fund except in exceptional circumstances.

In order to foster widespread competition, individual contracts for which bids are invited shall, whenever feasible, be of a size large enough to attract bids on an international basis. On the other hand, if it is technically and administratively possible to divide a project into contracts of a specialized character and such division is likely to be advantageous and to allow broader formal open international tendering the project shall be so divided.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantage for the borrower country.

Article II

Advertising and Prequalification

Section 2.01 Advertising :

On all contracts subject to formal open international tendering invitation to bid should be advertised in at least one newspaper of general circulation in the borrower's country. Copies of the invitation to bid for the advertisement should also be transmitted promptly to local representatives of the eligible source countries.

Section 2.02 Prequalification of Bidders :

In case the Fund recognises necessity of prequalification of bidders, the Fund requires the use of prequalification. It should be done taking into account (i) the experience and past performance of each firm on similar work, (ii) its capabilities with respect to personnel, equipment and plant, and (iii) its financial positions. Abbreviated specifications shall be made available to contractors desiring to be considered for qualification. When prequalification is employed, all firms which are found to be qualified shall be permitted to bid.

Article III

Bidding Documents

Section 3.01. Reference to the Fund ::

Bidding documents should refer to the following languages : ".....(name of borrower).....has received (or in appropriate cases 'has applied for') a loan from The Overseas Economic Cooperation Fund in towards the cost of (name of project)."

Section 3.02. Bid Bonds or Guarantees :

Bid bonds or bidding guarantees are usual requirement, but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid Bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

Section 3.03. Conditions of Contract :

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the borrower and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the borrower, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

Section 3.04. Clarity of Specifications :

Specifications should set forth as clearly and precisely as possible the work to be accomplished, the goods and services to be supplied and the place of delivery or installation. The drawings should be consistent with the text of the specifications; where they are not, the text shall govern. The specifications should identify the main factors or bases which will be taken into account in evaluating and comparing bids. Any additional information, clarification, correction of errors or alterations of specifications shall be sent promptly to all those who had requested the original bidding documents. Invitations to bid should contain an indication of the eligible source countries and any provision for permissible imports from non-eligible source countries.

Except where the Fund has agreed to procedures other than formal open international tendering (see Section 1.02) the specifications should be so worded as to permit and encourage the widest possible international bidding.

Section 3.05 Standards :

If national standards to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that goods meeting Japan Industrial Standard or other international accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

Section 3.06 Use of Brand Names :

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of a specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative goods which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

Section 3.07. Expenditures under Contracts :

As the use of the Fund's loan is limited to financing expenditures for goods produced in the territories of the eligible source countries, permissible imports from non-eligible source countries and services supplied from the eligible source countries, the bidding documents should require the contractor or supplier to limit his expenditures under the contract accordingly or to identify expenditures in non-eligible source countries in his statements or invoices.

For statistical purposes the Fund requires information concerning their geographical origin of the goods and services it finances and of their major components. The bidding documents should require the contractor or supplier to furnish the necessary information.

Section 3.08. Pricing of Bids :

As the Fund's loan is denominated in Japanese Yen, the bid price should be stated in Japanese on provided, however, that for the portion of the bid price which the bidder expects to spend in the borrower's country such portion should be stated in the borrower's currency.

Section 3.09. Contract Price :

The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

Section 3.10. Price Adjustment Clauses :

Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

In appropriate cases, provision should be made for adjustment (upwards or downwards in the contract prices in the event changes occur in prices of the major cost constituents of the contract, such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents so that the same provisions will apply to all bids.

A ceiling off prices adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

Section 3.11 Advance Payments :

The percentage of the total payment to be made in advance upon effectuation of the contract for mobilization expenses should be reasonable. Other advances to be made, as for example for materials delivered to the site for incorporation in the works, should also be clearly described in the bidding documents.

Section 3.12 Guarantees, Performance Bonds and Retention Money :

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

Section 3.13 Insurance :

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successfully bidder.

Section 3.14 Liquidated Damage and Bonus Clauses

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

Section 3.15 Force Majeure :

The conditions of contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate stipulating that failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract shall not be considered a default under the contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of contract.)

Section 3.16 Language Interpretation :

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to the such documents and it is required to specify which is governing.

Section 3.17 Settlement of Disputes :

Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of contract. It is appropriate that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which has been prepared by International Chamber of Commerce.

Article IV**Bid Opening Evaluation and Award of Contract :****Section 4.01 Time Interval Between Invitation and Submission of Bids :**

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 45 days should be allowed for international bidding. Where large civil works are involved, generally not less than 90 days should be allowed to enable prospective bidders to conduct investigations at the site before submitting their bids. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each project.

Section 4.02 Bid Opening Procedures :

The date, hour and place for latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bidders all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and total amount of each bid and of any alternative bids if they have been requested or permitted should be read aloud and recorded.

Section 4.03 Clarifications or Alteration of Bids :

No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The borrower may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask bidder to change the substance or price of his bid.

Section 4.04 Procedures to be Confidential :

Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning awards should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

Section 4.05 Examination of Bids :

Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains in admissible reservations or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

Section 4.06 Post-qualification of Bidders :

In the absence of prequalification, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

Section 4.07 Evaluation and comparison of Bids :

Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be

expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of the currencies before the award is made. In such cases the Exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

A detailed report on the evaluation and comparison of bids setting forth the specific reasons on which the determination of the lowest evaluated bid is based should be prepared by the borrower or by its consultants.

Section 4.08 Rejection of Bids :

Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the cost estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b) there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revisions of the specifications or modification in the project (or amount of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

Section 4.09 Award of Contract :

The award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities or work not stipulated in the specifications or to modify his bid.

After bids have been analyzed, copies of the analysis of bids and proposals for awards, together with the reasons for such proposals, shall be submitted to the Fund for approval.

Article V**Guidelines for the Use of Consultants :****Section 5.01 Independence of Consultants :**

Consultants firms employed in relation to a project financed under the Fund's shall be independent in the sense that their advice and the designs, specifications and tender documents prepared by them shall be free of national, commercial or industrial bias.

Consulting engineers who are associated with contracting or manufacturing firms shall be used only if they disqualify themselves and their associates for work in any other capacity on the same project. In the case of consulting engineers who are affiliates of manufacturers offering consulting services steps shall be taken not only to ensure that the company to which the consultant is affiliated will be disqualified from future bidding on any part of the project, but also that specifications will be impartial and can be complied with on a competitive basis.

Section 5.02 Selection of Consultants :

Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consulting firms. However, in the process of selection the borrower shall consider a reasonable number

of prospective firms, including those notified by the Fund, which can be expected to render competent and independent services from the eligible source countries. Invitations to submit proposals shall be extended to at least three firms. Proposals, when received, should first be qualitatively compared i.e. with respect to plans of approach, schedules, experience and capabilities of personnel to be assigned; after sanction of a firm or firms considered to be best qualified for the assignment has been made, negotiations to agree upon the price and other financial terms of the contract should be opened so as to reach the final decision. The Fund reserves the right to approve the choice of the consultant to be employed or already employed by the borrower for the preparation and supervision of the project financed by the Fund.

ANNEXURE III

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No. _____ Date : _____

To

The Controller of Aid Accounts and Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U.C.O. Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Subject : Import of _____ from Japan under
the Yen Credit No. ID-P. 7 (Project Aid for
1979-80.)

Sir,

In connection with the import of _____ from _____ under the above mentioned Yen Credit No. ID-P. 7 (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the _____ (name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

- (a) Name and Address of the Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- (g) Gross FOB value of contract (in Yen).
- (h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.
- (i) Net FOB value (In Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with overseas suppliers.
- (k) Name and Address of the Overseas Supplier :
 - (i) Nationality
 - (ii) Percentage of the share held by Nationals of the eligible source countries.
 - (iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier,
 - (iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.
- (l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (m) Expected date of completion of deliveries.

- (n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).
- (p) Name and address of the imports bank in India.
- (q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

ANNEXURE IV

(Letter of Authority Form)

No. F.

Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan Agreement No. I.D.-P. 7—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit :

Dear Sir,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen _____ as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interest as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the Suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/C against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto _____.

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to :—

1. Importer _____ with reference to their Letter No. _____ dated _____

2. Importers' Banker—They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9% per annum for the first thirty days and at the rate of 15% per annum for period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier/date of reimbursements to Bank of India and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is also required to be deposited into the Government of India Account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Suppliers and also the date on which rupee deposit is made into Government Account. (Any change in this rate will be intimated if and when made. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance).

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-68, 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit/Loan Agreement—Loans from the Government of Japan 4 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 7 for 1979-80.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent to them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas supplier bankers), if any, should be settled directly between the Indian bank and the Bank of India Tokyo Branch.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE V

Form OECF—LC I

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for goods)

Date :

To _____ This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. _____

dated _____
(Name and address of the Supplier)
between (Borrower) and The Overseas Economic Cooperation Fund.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of _____ for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of sign of yen _____ (Say yen _____) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents:

Signed commercial invoice in

Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight and Notify"

Other documents

cldencing shipment of [brlef description of goods to be shipped referring to Contract No. (if any)] from _____ to _____

Partial shipments are _____ permitted.

Transhipment is _____ permitted:

Bills of lading must be dated not later than

Drafts must be presented for negotiation not later than

All drafts and documents under this credit must be market "Drawn under _____ irrevocable credit No. _____ dated _____ and Import Reference No. (s) _____ if(any)".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

- After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued hereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordanc with instructions issued by the negotiating bank.
- The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to _____.
- All banking charges under this credit are for the account of suppliers.

Yours faithfully,

.....
(a commercial bank)

By :

.....
(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS :

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____

I. Initial Payment.

Amount _____
being _____ % of the total
contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount _____
being _____ % of the total
contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount _____
being _____ % of the total
contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment
against shipping documents.

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's statement is required instead of the above-mentioned Statement of Performance.

2. After obtaining the reimbursement for your payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the abovementioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the draft shall be sent to us immediately after the receipt thereof.

4. All banking charges under this credit are for the account of the suppliers.

Yours faithfully,

(A commercial bank)

By :

(Authorised Signature)

PAYMENT SCHEDULE:

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____

I. Initial Payment

Amount _____
being _____ % of the total contract price
Required documents : beneficiary's Statement
Latest presentation date :

II. Progress Payment.

Aggregate amount _____
being _____ % of the total contract Price to be paid as follows :

	Amount due	Latest presentation date
Ist Instalment	_____	_____
2nd Instalment	_____	_____
.....

Required document : a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date :
Ref. No.

To

_____(Name and address of the
Supplier)

Re: Letter of Credit No. _____ dated,

To _____
This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. _____, dated _____, between (Borrower) and The Overseas Economic Cooperation Fund.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of _____ (Say Yen available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us).

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. _____ with regard to _____ Project). Drafts must be presented for negotiation not later than _____.

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. _____ dated _____".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

issued by _____
for _____ in favour
of _____ concerning _____ Pro-
ject under Loan Agreement No. _____

No. _____, dated _____ between _____
and _____
(Borrower)

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle _____ to receive the sum of _____ (Yen _____ only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract

By _____
(Authorised Signature)

Special Instructions.

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.